सार फील्ड दौरे किए जाते हैं। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी की शासी निकाय में अन्य लोगों के अलावा, स्थानीय विधायकों तथा सांसदों को भी शामिल किया जाता है। कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की समीक्षा करने के लिए शासी निकाय की सामान्यतः तिमाही बैठकें होती हैं।

राज्य स्तर पर कार्यक्रमों की निगरानी के लिए राज्य स्तरीय समन्वय समिति गठित की गई है। राज्य स्तर पर मुख्यालय में कार्यक्रम की प्रभावी निगरानी और मूल्यांकन करने के लिए परियोजना निर्धारण एवं निगरानी सैल का भी गठन किया गया है। केन्द्र स्तर पर मंत्रालय द्वारा आवधिक प्रगति रिपोर्टों, कार्यशालाओं, समीक्षा बैठकों और उसके अधिकारियों द्वारा फील्ड दौरों की मार्फत कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करने के लिए एक सतत् प्रणाली तैयार की गई है।

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम और जवाहर रोजगार योजना के कार्य निष्पादन का मूल्यांकन करने और उनमें सुधार लाने हेतु उपाय करने के लिए कई प्रतिष्ठित अनुसंधान संगठनों को शामिल करके मंत्रालय द्वारा कार्यक्रमों का समवर्ती मूल्यांकन भी किया जाता है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के समवर्ती मूल्यांकन के तीन दौर पूरे हो गए हैं और चौथे दौर का फील्ड कार्य प्रगति पर है। जवाहर रोजगार योजना के पहले समवर्ती मूल्यांकन का फील्ड कार्य हाल ही में पूरा हुआ है और रिपोर्टों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

इसी प्रकार आवधिक रिपोर्टों तथा विवरणियों, फील्ड दौरों और समीक्षा बैठकों की मार्फत विभिन्न स्तरों पर ग्रामीण विकास के अंतर्गत अन्य योजनाओं की भी निगरानी की जाती है।

गांवों में टूटी-फूटी सड़कों का पुनर्निर्माण किया जाना

1329. **श्री रामजी लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गांवों में टूटी-फूटी सड़कों का पुनर्निर्माण करने संबंधी कोई विशेष योजना आरम्भ की है;

(ख) क्या सरकार इस योजना का क्रियान्वयन गांवों में लिंक रोड का निर्माण करने के लिए स्वीकृत की गई धनराशि के अलावा और धनराशि से करने का विचार रखती है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

(ग) क्या सरकार गांवों में पंचायत की जमीन पर जबरदस्ती किए गए कब्जों को हटाने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है; यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तमभाई पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण विकास मंत्रालय का गांवों में पंचायत की जमीन पर जबरदस्ती किए गए कब्जों को हटाने का कोई प्रस्ताव नहीं है क्योंकि यह राज्य का विषय है।

हरियाणा के बड़े गांवों से पानी की निकासी के लिए योजनाएं

1330. **श्री रामजी लाल** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कुछ नई योजनाएं बनाई गई हैं तथा जवाहर रोजगार योजना के अधीन बड़े गांवों से पानी की निकासी के लिए राज्य सरकारों को और अधिक धन उपलब्ध कराया गया है,

(ख) यदि हां, तो इनका ब्यौरा क्या है और इन योजनाओं के अंतर्गत हरियाणा राज्य को कितनी राशि आवंटित की गई है, और

(ग) क्या जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत हरियाणा के विभिन्न गांवों में ये योजनाएं आरम्भ की गई हैं, यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान हिसार और कुरुक्षेत्र जिलों में इन योजनाओं के संबंध में ब्यौरा क्या है ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री रामेश्वर ठाकुर) : (क) और (ख) जवाहर रोजगार योजना वर्ष 1989-90 से चल रही है। यद्यपि,

जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बड़े गांवों से जल की निकासी के लिए कोई विशिष्ट निधियां उपलब्ध नहीं कराई जाती हैं, फिर भी ग्राम पंचायतें और जिला ग्रामीण विकास एजेंसियां/जिला परिषदें लोगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तथा जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार जल निकासी से संबंधित कार्य कर सकती हैं। जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1992-93 के लिए हरियाणा को राज्य के मौचिंग अंश के 375.86 लाख रुपए सहित 1879.28 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है ।

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत 1992-93 के लिए हिसार और कुरूक्षेत्र जिलों को क्रमशः 149.59 लाख रुपए और 56.63 लाख रुपए की राशि रिलीज की गई है ।

New schemes for creation of rural employment

1331. SHRI SOM PAL : Will the PRIME MINISTER be pleased to state :

(a) whether a new scheme for generation of rural employment has recently been launched by Government;

(b) if so, what are the details thereof and what steps are being taken to ensure that funds and benefits under these schemes reach the targeted areas and people; and

(c) what are the new features incorporated in the scheme as compared to the previous such schemes ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI RAMESHWAR THAKUR) : (a) & (b) No Sir. However, Jawahar Rozgar Yojana (JRY) the primary objective of which is to generate gainful employment for unemployed and underemployed men and women in the rural areas is being implemented at national level. An amount of Rs. 18400 crores have been approved for implementation of JRY during the 8th Plan. It has been the objective of JRY to create a minimum of 1000 million mandays each year in the 8th Five Year Plan Period. This will be in the form of supplementary employment. To ensure that the funds and benefits under JRY reaches the targeted areas and the people, the implementation of the scheme is being regularly monitored by the Central Government through monthly, quarterly and annual progress reports received from the State Governments. The State Governments have also drawn up a schedule of inspection for each supervisory level officer at the State/District/Block level to review the qualitative and quantitative aspects of the scheme. The Government of India also convenes Meetings with the State Governments periodically to review the programme with a view to effecting improvement in the quality of implementation.

(c) Under JRY, it is proposed to launch an intensified JRY in 100-120 backward districts where the need for employment is more, when compared to other districts out of overall JRY allocations during the year 1993-94. The details of this scheme are being worked out.

बेकार पड़ी भूमि पर वृक्षारोपण

1332. **श्री सोमपाल** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का बेकार पड़ी भूमि पर वृक्ष लगाने का विचार है;

(ख) यदि प्रतिवर्ष कितनी भूमि पर और किन-किन स्थानों पर वृक्षारोपण किया जाएगा; और

(ग) क्या वृक्षारोपण में उपयोगी पौधे को प्राथमिकता दी जाएगी ?

ग्रामीण विकास मंत्रालय (परती भूमि विकास विभाग में राज्य मंत्री (कर्नल राम सिंह) : (क) जी, हां । उस प्रयोजन के लिए बनाई गई विभिन्न वृक्षारोपण योजनाओं के अंतर्गत सरकार द्वारा वृक्षारोपण गतिविधि सहित बंजर भूमि का सतत् विकास किया जा रहा है ।

(ख) देश में बंजर भूमि सहित विभिन्न प्रकार की भूमि पर वृक्षारोपण के लक्ष्यों को केन्द्र और राज्य योजनाओं के तहत निधियों की